

भारतीय संसद में गैर-सरकारी सदस्यों के वधियकों की अस्वीकृति

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में, [संसद सदस्यों](#) की स्वतंत्र अभिव्यक्तिके लिये महत्त्वपूर्ण [गैर-सरकारी वधियकों](#) को सीमति समय आवंटन के कारण भारत की संसद में अस्वीकृत कर दिया गया है।

- [17वीं लोकसभा \(जून 2019 से फरवरी 2024\)](#) में इन वधियकों पर वचिर-वमिरश में कमी देखी गई, जससे [व्यक्तगत सांसदों की घटती भूमिका](#) और [संसदीय लोकतंत्र](#) के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा उत्पन्न हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों का वधियक क्या है?

- **परचिय:** गैर-सरकारी सदस्यों के वधियक उन सांसदों द्वारा प्रस्तावति कयि जाते हैं जो **मंत्रि नहीं होते** (अर्थात सरकार का हसिसा नहीं होते), जससे उन्हें अपने नरिवाचन कषेत्रों के लयि **महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कानून या संशोधन प्रस्तुत** करने की अनुमति मिलति है।
- **मुख्य वशिषताएँ:** केवल गैर-सरकारी सदस्य ही इन वधियकों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जससे स्वतंत्र वधियी प्रस्तावों को अवसर मलित है।
 - सांसद **वशिषिट मामलों** पर ध्यान आकर्षति करने के लयि प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **प्रक्रया:**
 - प्रस्ताव तैयार करना और नोटसि देना: सांसद कम से कम एक महीने के नोटसि पर वधियक का प्रस्ताव तैयार करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं।
 - परचिय: वधियक संसद में पेश कयि जाते हैं, उसके बाद प्रारंभिक चर्चा होती है।
 - बहस: यदाचयन हो जाता है, तो वधियकों पर बहस की जाती है, आमतौर पर शुक्रवार दोपहर को सीमति सत्रों में।
 - नरिणय: वधियक वापस लयि जा सकते हैं या मतदान के लयि आगे बढ़ाए जा सकते हैं।
- महत्त्व: ये वधियक सांसदों को दलीय दबाव के बनिा, प्राय: महत्त्वपूर्ण या वविदास्पद मुद्दों पर अपनी बात कहने का मंच प्रदान करते हैं।
 - इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण **वर्ष 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री** की मृत्यु के बाद **एच.वी. कामथ** द्वारा प्रस्तुत वधियक है, जसमें **संवधिन में संशोधन करके केवल लोकसभा सदस्यों को ही प्रधानमंत्री पद के लयि पात्र** बनाने का प्रयास कयि गया था।
 - स्वतंत्रता के बाद से अब तक **केवल 14 गैर-सरकारी वधियक** पारति कयि गये हैं, तथा **वर्ष 1970 के बाद से कोई भी वधियक पारति नहीं हुआ है**।
 - [ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार वधियक, 2014](#), 45 वर्षों में राज्यसभा द्वारा अनुमोदति पहला गैर-सरकारी सदस्यों का वधियक था, लेकिन यह लोकसभा में पहुँचे बनिा ही व्यपगत हो गया।

सरकारी वधियक बनाम गैर-सरकारी वधियक

सरकारी वधियक	गैर-सरकारी वधियक
इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत कयि जाता है।	यह मंत्री के अतरिकित कसिी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत कयि जाता है।
यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शति करता है।	यह वपिक्ष की नीतियों को प्रदर्शति करता है।
संसद में इसके पारति होने की संभावना अधिक होती है।	संसद में इसके पारति होने के संभावना कम होती है।

संसद द्वारा सरकारी वधियक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।	इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
सरकारी वधियक को संसद में पेश होने के लिये सात दिनों का नोटिस होना चाहिये।	इस वधियक को संसद में पेश करने के लिये एक महीने का नोटिस होना चाहिये।
इसे संबंधित विभाग द्वारा वधिविभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है।	इसे संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है।

सरकारी सदस्यों के वधियकों में कमी क्यों आई है?

- **समय की कमी:** PRS लेज़सिलेटिव रिसर्च के आँकड़ों से पता चलता है कि 17वीं लोकसभा में गैर-सरकारी सदस्यों के वधियकों पर सरिफ 9.08 घंटे जबकि राज्य सभा में 27.01 घंटे का व्यय हुआ, जो कुल सत्र के घंटों का एक अंश है।
 - 18वीं लोकसभा के दो सत्रों में नचिले सदन में ऐसे वधियकों पर केवल 0.15 घंटे तथा राज्य सभा में 0.62 घंटे व्यय किये गए, तथा प्रस्तावों पर सबसे कम समय लगा।
 - शुक्रवार को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की तथि निर्धारित होने से चर्चा सीमित हो जाएगी, क्योंकि कई सांसद अपने नरिवाचन कक्षेत्रों में चले जाएँगे, जिससे चर्चा के लिये समय और कम हो जाएगा।
 - इन वधियकों की लोकप्रियता में गरिावट का कारण सांसदों की गंभीरता की कमी को माना जा सकता है, क्योंकि कई सांसद चर्चाओं में भाग ही नहीं लेते।
- **गैर-सरकारी सदस्यों के वधियकों को पुनः शुरू करना:** गैर-सरकारी सदस्यों के वधियकों को सप्ताह के मध्य में स्थानांतरित करने से भागीदारी और चर्चा को बढ़ावा मलि सकता है।
 - सांसदों को उनके प्रस्तावति उपायों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना तथा संसद में स्वतंत्र भाषण के मौलिक अधिकार की रक्षा करना।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

2017-2018:

भारत की संसद के संदर्भ में, नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजयि:

1. गैर-सरकारी वधियक ऐसा वधियक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो नरिवाचति नहीं है कनि्तु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनरिदषिट है।
2. हाल ही में, भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर-सरकारी वधियक पारति किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- कानून बनाने की प्रक्रिया संसद के कसिी भी सदन में वधियक पेश किये जाने से शुरू होती है। वधियक को मंत्री या मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य पेश कर सकता है। पहले मामले में इसे सरकारी वधियक कहा जाता है और दूसरे मामले में इसे गैर-सरकारी सदस्य का वधियक कहा जाता है।
- दूसरे शब्दों में, एक गैर-सरकारी सदस्य का वधियक कसिी मंत्री के अलावा संसद के कसिी भी सदस्य (नरिवाचति या मनोनीत) द्वारा पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने से पहले एक महीने की नोटिस अवधि की आवश्यकता होती है। इसका मसौदा तैयार करना उस सदस्य की एकमात्र ज़मिमेदारी है जो वधियक पेश करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- संसद द्वारा पारति पहला गैर-सरकारी वधियक मुसलमि वकफ वधियक, 1952 था, जिसका उद्देश्य वक्फों का बेहतर शासन और प्रशासन प्रदान करना था। इसे वर्ष 1954 में पारति किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- वर्ष 2015 में राज्य सभा द्वारा पारति ट्रांसजेंडर वयक्ति (अधिकारों का संरक्षण) वधियक, 2014 पछिले 45 वर्षों में राज्य सभा की स्वीकृत पाने वाला पहला गैर-सरकारी वधियक बन गया। अतः वकिलप (d) सही उत्तर है।

